International Journal of Advance and Applied Research (IJAAR)
Peer Reviewed Bi-Monthly

ISSN – 2347-7075
Impact Factor –7.328
Vol.9 Issue.3 Jan–Feb- 2022

वित्तीय समावेशन:-चुनौतियॉं व समाधान

[१]विरेन्द्र कुमार सैनी [२]वरूण कुमार
[१ २]सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल, जनपद पौडी गढवाल, राज्य-उत्तराखण्ड पिन-२६६१९३
agmsaini1981@gmail.com

शारांश:- वर्ष २०११ की जनगणना के अनुसार देश में सिर्फ ५९ प्रतिशत परिवारों को बैंकिगं सुविधा उपलब्ध है। शहरों में ६८ प्रतिशत और गांव में ५४ प्रतिशत परिवारों की पहुंच ही बैंकिगं सुविधा तक थी। जिससे स्वत: स्पष्ट हो जाता है कि आबादी का एक बडा हिस्सा बैंकिगं सुविधाओं से अछूता होने के कारण गरीबी के कुचक्र से बहार नहीं निकल पाया है, जिस कारण कोई भी मजबूरी होने पर यह साहूकारों के चंगुल में फॅस जातें है। गरीबों को वित्तीय रूप से अलग थलग रखकर कोई भी देश स्थायी प्रगति नही कर सकता है। वैश्विक स्तर की विभिन्न सस्थाओ जी-२०, विश्व बैकं तथा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी वित्तीय समावेशन को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण नियामक माना है। वित्तीय समावेशन का मुख्य उदेश्य ग्रामीणों को बैंकिगं सेवाएं प्रदान कर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोडना व शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को बैंकिगं सेवाएं प्रदान करना है। जिससे सम्पूर्ण देश का समतामूलक विकास सुनिश्चित हो सकें जिसमें समता का भाव हो जो भेद भाव रहित हो, जिसमें विषमता न हो एवं जिसमें किसी का शोषण न हो।

यह शोध पत्र वित्तीय समावेशन के अभाव के कारण होने वाली असमानताओं और उन असमानताओं को दूर करने के लिए उठाये गये सुधारात्मक उपाय पर ध्यान केंद्रित करता है जिससे हमारे राष्ट्र का समतामूलक विकास सुनिश्चित हो सके और देश वित्तीय समावेशन की विकास नीतियों से लाभांवित हो सके।

कुंजी शब्द:- , वित्तीय समावेशन, समतामूलक विकास , चुनौतियां, सुधारात्मक उपाय।

प्रस्तावना:-किसी भी देश के आर्थिक विकास का मुख्य आधार उस देश का बुनियादी ढॉचा होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति भी आर्थिक विकास के लाभों को ले सकें अर्थात कोई भी वयक्ति आर्थिक सुधारों से वंचित न रहें। जो वित्तीय समावेशन से ही संभव हो सकता है जिसके महत्व को स्वीकार करते हुए भारत सरकार द्वारा डिजिटल भारत अभियान प्रारंभ किया गया । भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के उदेश्य से इस कार्यक्रम की नीव रखी गई। वित्तीय समावेशन और डिजिटल भारत के सम्मिलित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही **जैम त्रयी** (जनधन आधार मोबाइल) योजना की आधारशिला रखी गई। वित्तीय समावेशन की जैम त्रयी योजना के द्वारा कोविड १९ के दौरान जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुॅचाने में सराहनीय भूमिका रही है।

वर्तमान में वित्तीय समावेशन की जो परिभाषा उपयोग में है वह है औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वंचित और अल्प आय वर्ग समूहों को सस्ती लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। वित्तीय सेवाओं में, औपचारिक वित्तीय प्रणाली

से जो वर्ग समूह वंचित है। उन समस्त वर्ग समूह के प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाओं की सुगम पहुँच का प्रावधान करना है

वित्तीय समावेशन से संबंधित चुनौतियॉं:-

१-सभी की बैकों तक पहुँच नहीं:- विश्व बैकं की एक रिर्पोट के अनुसार भारत मे लगभग १९० मिलियन वयस्कों के पास बैकं खाता नहीं है, जिससे भारत चीन के बाद गैर बैंकिंग आबादी में दुनिया का दूसरा सबसे बडा देश बन गया है।

२-डिजिटल डिवाइस का मंहगा होना:- कम आय वाले उपभोग्ता जो डिजिटल सेवाएं का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। साथ ही इन लोगों में डिजिटल कौशल की भी कमी है।

३- वित्तीय समावेशन में लैंगिक अंतराल:-ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट २०१७ के अनुसार भारत में १५ वष से अधिक आयु के ८३ प्रतिशत पुरूषों के अपेक्षा ७७ प्रतिशत महिलाओं ने ही किसी वित्तीय संस्थान में खाते का संचालन किया। जिससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन में महिलाओं की भागेदारी पुरूषों के सापेक्ष बहुत कम है।

४- **वित्तीय साक्षरता की कमी:-**वित्तीय समावेशन में वित्तीय साक्षरता की कमी सबसे बडी बाधा है जिसकी आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय रिर्जव बैकं ने वित्तीय साक्षरता नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उदेश्य केंद्रीय बैकं और सामान्य बैकिगं के बारे में स्कूल और कॉलेज के छात्रों , महिलाओं , ग्रामीण और शहरी गरीब, और वरिष्ठ नागरिकों कों वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ सिक्योरिटी ने पॉकेट मनी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में वित्तीय साक्षरता को बढावा देना है।

५- नकद आधारित अर्थव्यवस्था :- भारत में डिजिटल भुगतान अपनाना अपनें में एक चुनौती है भारत नकदी आधारित अर्थव्यवस्था है जो लेन देन के लिए नकदी पर निर्भर रहतें है जिस कारण डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए एक बाधा है।

भारतीय रिर्जव बैकं द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए उठाए गए कदम:- भारतीय रिर्जव बैंक वित्तीय समावेशन की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। सन १९६५ में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, १९६९ में और १९८० में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण, १९७० में अग्रणी बैंक योजना का क्रियान्वयन, १९७५ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना, १९९२ में स्वयं सहायता समूह बैंक कार्यक्रम की शुरूआत और २००१ में किसान कार्ड की शुरूआत आदि इसके उदहारण है।

वित्तीय समावेशन योजना का आकॅडो द्वारा विशलेषण:-

वितरण	मार्च २०१० को समाप्त वर्ष	मार्च २०१६ को समाप्त वर्ष	मार्च २०१७ को समाप्त वर्ष	अप्रैल २०१६ से मार्च २०१७ तक प्रगति ल
गांवों मे बैंकिगं केन्द्र- शाखाएं	३३३७८	५१८३०	५०८६०	-९७०

गांवो में बैंकिगं केन्द्र -शाखा रहित मोड	३४३१६	७३४४७७	७४७२३३	१२७७६
गंवो में बैंकिंग केन्द्र -कुल	६७६९४	७८६३०७	७९८०९३	११७८६

संर्दभ- भारतीय रिर्जव बैंक, वार्षिक रिर्पाट २०१६-२०१७।

भारतीय रिर्जव बैकं ने अप्रैल २००७ के अपने वार्षिक नीति में वित्तीय वंचन की समस्या को स्वीकार किया है और उसके लिए सकारात्मक उपाय आरंभ किए है वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उद्धेश्य से की जाने वाली कुछ मुख्य पहलों में निम्नलिखित शामिल है:-

१- नो फ्रिल बचत खाते प्रांरभ किये गयें, जिनमें या तो शून्य अथवा बहुत कम शेष अपेक्षित है और साथ ही प्रभार भी बहुत कम है, जिस कारण ऐसे खातें जनता के बडे वर्ग तक पहुंच सुगम बनाते है।

२- बैंकों द्वारा ग्रामीण परिवारो की उनके नकदी प्रवाह के आधार पर ऋण तक बिना झंझट के पहुंच सुगम बनाने के लिए २७००० रूपए तक की परिक्रामी ऋण सीमा के साथ, ही क्रडिट कार्ड योजना को जारी किया जाने से वित्तीय समावेशन की दिशा में सकारात्मक कदम था।

३-भारतीय रिर्जव बैकं ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं की व्यवस्था में सुधार लाने के उद्धेश्य से एक उप गवर्नर की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए वित्तीय क्षेत्र योजना पर एक समिति का गठन किया है जिससे उपरोक्त क्षेत्र में वित्तीय समावेशन को बहेतर बनाया जा सकें।

नाबार्ड द्वारा वित्तीय समावेशन के विकास के लिए उठाए गए कदमः-

नाबार्ड ने ऐसी अनेक पहलों को कार्यान्वित किया है जिन्होनें न केवल निर्धनों के वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण योगदान किया है , अपितु उनकी विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की जीवन की निर्वाह स्थितियों में भी सुधार कर दिया है। जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका स्वंय सहायता समूह बैको की ं रही है। नाबार्ड बैकं अनौपचारिक रूप से वित्तीय समावेशन के उद्धेश्य अर्थात समावेशी वित्त विकास को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।

कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्की मॉडलः- अधिक वित्तीय समावेाशन सुतिश्चित करने और बैंकिग क्षेत्र की पहुच में वृद्धि करने के उद्धेश्य से बैकों को कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्की मॉडल का उपयोग करते हुए वित्तीय और बैंकिग सेवाएं प्रदान करने के लिए मध्यवर्तियों के रूप में गैर सरकारी संगठनो स्वयं सहायता समूहो , सूक्ष्म वित संस्थाओं और अन्य सिविल सोसायटी संगठनो की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। इससे पहलें यह अनुमान लगाया गया था कि अब तक देश में केवल २७ प्रतिशत भारतीय कृषक परिवारों की पहुँच ही संस्थागत उधार त क है अन्य २२ प्रतिशत साहूकारों पर निर्भर करते है तथा शेष ५१ प्रतिशत की पंहुच किसी संस्थागत उधार तक नही ं है और वे कृषि तथा अन्य क्रियाकलाप जारी रखने के लिए अपनी निधि सम्बन्धी आवश्कयताओं को स्वयं किसी न किसी प्रकार पूरा करतें है। जिससे स्वंय स्पष्ट हो जाता है कि बैंकिग और वित्तीय

सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक और ऐसे लोगों तक औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अभी तक वंचित है और यह कार्य इतना कठिन है कि केवल बैंकं इस कार्य को पूरा नही ंकर सकतें है जिसके समाधान के लिए कारोबार सुसाधक और कारोबार संपर्की मॉडल को अपनाकर ही किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक व्यक्तियों के लिए, बचत, ऋण, बीमा, भुगतान और प्रेषण सुविधाओं की सुगम पहुँच का प्रावधान करना है।

कारोबार संपर्की का विचार ब्राजील से आया है, जहॉ फुटकर विक्रेता , लाटरी की दुकानें और डाकघर बैंक शाखाओं का भी कार्य करते है वर्ष २००७ में ब्राजील के ९०००० अभिकर्ताओं के माध्यम से बॉयो मैट्रिक या स्मार्ट कार्ड रीडर जैसी बिक्री केन्द्र आदि उपायों के द्वारा अनुमानित रूप से दस करोड डालर का लेनदेन किया गया था और केवल तीन वर्ष की अवधि में इस नेटवर्क में लगभग १.२ करोड खाते खोले गए थे।

कारोबार संपर्की कौन बन सकता है:-कारोबार संपर्की के रूप में निम्नलिखित कार्य कर सकते है।

१-गैर सरकारी संगठन

२- सोसाइटी अधिनियम के अधीन गठित सूक्ष्म वित संस्थाएं।

३- राज्यों के सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अधीन गठित सोसाइटी।

४- कंपनी अधिनियम १९५६ /२०१३ के अधीन पंजीकृत कंपनियां।

५- पंजीकृत एन०बी०एफ०सी कंपनियां।

६-डाकघर।

७- बीमा अभिकर्ता।

८-कृषि विज्ञान केन्द्र।

९-खादी ग्रामाद्योग।

१०- पंजीकृत ग्राम संगठन।

११- सेवानिवृत बैंकं कर्मचारी।

१२-पूर्व सैनिक

१३-सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी।

विश्व बैंक की वैश्विक वित्तीय समावेशन डेटाबेस रिपोर्ट व ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट २०१७ के अनुसार वर्ष २०१४ में अनुमानित ५३ प्रतिशत भारतीय वयस्कों के अपेक्षा वर्तमान में ८० प्रतिशत वयस्कों के पास एक बैंक खाता है।

प्रधानमंत्री जन-धन योंजना वित्तीय समावेशन का राष्ट्रीय मिशन ने अपने सफल कार्यान्वयन के सात वर्ष पूरे कर लिए है पीएमजेडीवाई की शुरूआत के बाद से अबतक इसके तहत कुल ४३.०४ करोड से अधिक लाभार्थियों के बैंकं

खातों में १४६२३१ करोड रूपये भेजे गए। क ुल खाताधारकों में ५५ प्रतिशत जन-धन खाताधारक महिलाएं है और ६७ प्रतिशत जन-धन खाते ग्रामीण और अर्द्ध शहरी इलाकों मे है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला पीएमजेडीवाई खाताधारको के खातों में कुल ३०९४५ करोड रूप्ये जमा किए गए साथ ही लगभग ५.१ करोड खाताधारक विभिन्न योजनाओं के तहज सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्राप्त करतें है।

निष्कर्षः- उपरोक्त शोधपत्र से स्पष्ट होता है किसी भी राष्ट्र के लिए वित्तीय समावेशन समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मदद करता है, इससे बचत, निवेश में वृद्धि होती है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करता है और बुनियादी औपचारिक वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक प्रत्येक नागरिक सुनिश्चित करता है। भारत सरकार के द्वारा इसके महत्व को देखते हुए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति २०१९ह-२०२४ और वित्तीय शिक्षाण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति २०२०-२०२५ का वित्तीय जागरूकता लाने के उद्धेश्य से गठन किया गया। वित्तीय समावेशन से सूक्ष्म, लघु, और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के लिए ऋण के प्रवाह को बढावा मिला है। सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडे वर्गो सीधे लाभ दिया जा रहा है । भारत में कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक ऋण सरल पहुँच के किसान कार्ड के माध्यम से दिया गया है जिससे कृषि क्षेत्र का सर्म्पूण विकास सुनिश्चित हो सकें। वस्तुतः यही कारण है कि वित्तीय समावेशन के द्वारा ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अंतिम छोर पर खडें व्यक्ति को भी आर्थिक विकास का लाभ पहुँचया जा सकता है।

संदर्भ सूचिः-

1. ओझा, बी.एल. मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व ै ६७ शिवाजी नगर जयपुर २०१०
2. कुमार , अविनाश, वित्तीय समावेश व वित्तीय साक्षरता में राजभाषा हिन्दी का योगदान ,आधार सितम्बर २०१०
3. कुमार शर्मा सुधीर देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की भूमिका मार्च २०१२
4. www.cds.edu
5. www.wikipedia.org
6. www.pmjandhanyojana.co.in
7. www.pmjdy.gov/scheme_detail.aspx